पीसी ज्वेलर एक्सपोर्ट डिवीजन को करेगी अलग

नई दिल्ली, प्रेट्र : पीसी ज्वेलर लिमिटेड (पीसीजेएल) ने कहा कि उसके बोर्ड ने एक्सपोर्ट डिवीजन को अलग करने और संपूर्ण सहायक कंपनी पीसीजे जेम्स एंड ज्वेलरी लिमिटेड में उसका विलय किए जाने की मंजूरी दे दी है। कंपनी के बोर्ड ने शनिवार को हुई बैठक में यह मंजूरी दी। इस व्यवस्था के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार के एनसीएलटी, सेबी, शेयर बाजारों, शेयरधारकों तथा अन्य संस्थानों से भी मंजूरी लेने की जरूरत होगी।

एनबीएफसी सेक्टर में चुनिंदा बड़ी कंपनियों के दांव विफल रहे और पूरा सेक्टर कर्ज संकट में आ गया। वर्तमान में सेक्टर बेहद गंभीर स्थिति में है।

— इंजेती श्रीनिवास
सचिव, कॉरपोरेट मामले

तैयारी ▸ बिक्री प्रक्रिया पूरी करने के लिए छोटी पीएसयू के लिए चार, बड़ी के लिए छह महीने की बन रही समय सीमा

सरकारी कंपनियों के विनिवेश में आएगी तेजी

अधिक समय लगने की सूरत में प्रक्रिया को रद्द करने का भी है प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सब कुछ ठीक रहा और वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली तो सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया चार महीने में पूरी हो जाएगी। मंत्रालय ने विनिवेश के इस तरीके के तहत सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री में लगने वाले समय को घटाने के लिए प्रक्रियागत बदलावों की कवायद शुरू की है। इसके तहत प्रस्तावित निवेशक को बिक्री डाक्यूमेंट जारी किये जाने के चार महीने के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रावधान करने का प्रस्ताव है।

माना जा रहा है कि रणनीतिक बिक्री में लगने वाला समय ही अभी इस तरीके से होने वाले विनिवेश की सबसे बड़ी अड़चन है। यही वजह है कि निवेशक भी अभी तक इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने से कतराते रहे हैं। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इसलिए छोटे आकार वाले पीएसयू की रणनीतिक बिक्री में लगने वाले समय को कम करके चार महीने लाने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता एयर इंडिया जैसे बड़े आकार वाली सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री के लिए छह माह की समय सीमा तय करने का विचार है।

अभी इस काम के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। यही वजह है कि कुछ मामलों में काफी लंबा समय लग जाता है। मंत्रालय का मानना है कि अगर किसी सरकारी कंपनी की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया को तीन से चार महीने में पूरा नहीं किया जाता है तो उस प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए।

चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में 90,000 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी विनिवेश लक्ष्य रखा है। इसे पाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट (डीआइपीएएम) का पूरा जोर सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री के जरिए विनिवेश करने पर है। नीति आयोग ने इसके लिए लाभ अर्जित करने वाले और घाटे में चल रहे दोनों तरह के 35 सार्वजनिक उपक्रमों की सूची तैयार की है।

सूत्र बताते हैं कि प्रक्रिया इस प्रकार की तैयार की जा रही है कि एक बार में एक से अधिक सरकारी कंपनियों की रणनीतिक बिक्री की कवायद शुरू की जा सके। जिन कंपनियों को रणनीतिक बिक्री के लिए चुना गया है उनमें एयर इंडिया, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स और सेल की भद्रावती, सलेम और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक समेत कुछ सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री के प्रस्ताव को सरकारी मंजूरी का इंतजार है।

कुछ कंपनियों में रणनीतिक बिक्री की शुरुआत साल 2017 में और कुछ में 2018 में हुई थी। लेकिन अभी तक किसी सौदे को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है। बीते वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश से 84,972 करोड़ रुपये की राशि जुटाई थी, जिसमें 15,194 करोड़ रुपये रणनीतिक बिक्री के जरिये आए थे।

क्या है 'एमसीए-21'

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली

- 'एमसीए-21' पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी
- जीडीपी की नई सीरीज में किया गया है 'एमसीए-21' डेटाबेस का इस्तेमाल

हमारे देश में कंपनियों का पंजीकरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) द्वारा होता है, जो कंपनी मामलों के मंत्रालय (एमसीए) में आता है। मंत्रालय ने कंपनियों के पंजीकरण से लेकर उनके बारे में हर जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसे 'एमसीए-21' कहते हैं। इसके नाम में 21 का आशय 21वीं सदी से है। यह ऐसा पोर्टल है जहां कंपनियों का पंजीकरण होता है और पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न, बैलेंस शीट, नाम व पते में बदलाव और निदेशकों का ब्योरा सहित सभी जरूरी दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही फाइल कर सकती हैं। एक प्रकार से यह इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का काम करता है। इन सूचनाओं को सहेजकर रखने के लिए दिल्ली में एक डाटा सेंटर, जबकि एक डिजास्टर रिकवरी सेंटर चेन्नई में स्थापित किया गया है। चेन्नई स्थित यह सेंटर किसी भी आपात स्थिति में बैक-अप का काम करता है। 'एमसीए-21' पर उपलब्ध सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं और एक निश्चित फीस देकर कोई भी इन्हें देख सकता है। सरकार की ओर से दी जा रही विभिन्न सेवाओं जैसे डिजिटल सिग्नेचर और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करने के लिए भी इस पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। जो भी कंपनी आरओसी में रजिस्टर्ड है उसके वित्तीय लेखाजोखा को इस पोर्टल पर देखा जा सकता है। फिलहाल देश में 18 लाख से अधिक कंपनियां पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से मात्र 11.16 लाख कंपनियां ही सक्रिय हैं। अगर कोई कंपनी लगातार तीन साल तक वित्तीय लेखाजोखा दाखिल नहीं करती है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाता है।

एमसीए-21 में दाखिल किए गए उनके सालाना एकाउंट्स के आधार पर ही सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस (सीएसओ) फिलहाल जीडीपी की नई सीरीज (आधार वर्ष 2011-12) में खनन, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र के जीडीपी का आकलन कर रहा है। पुरानी जीडीपी सीरीज (आधार वर्ष 2004-05) में प्राइवेट कॉरपोरेट क्षेत्र के जीडीपी का अनुमान रिजर्व बैंक की कंपनियों की वित्तीय स्थिति के अध्ययन के आधार पर लगाया जाता था। इसके तहत आरबीआइ हर साल 2,500 कंपनियों के वित्तीय परिणामों का अध्ययन करता था।

ताजा विवाद उस समय खड़ा हुआ जब एनएसएसओ ने इस डाटाबेस में शामिल कंपनियों का सर्वे कर एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एमसीए-21 डाटाबेस में से 34,456 उद्यमों का सर्वे करने के बाद पता चला कि 39 फीसद उद्यम 'आउट ऑफ सर्वे' हैं, 21 फीसद उद्यम 'आउट ऑफ कवरेज' व 12 फीसद उद्यम 'नॉन-ट्रेसेबल' (जिनके बारे में कुछ पता नहीं) हैं।

इस रिपोर्ट के बाद जीडीपी के अनुमान लगाने में 'एमसीए-21' डाटाबेस के इस्तेमाल पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पूर्व मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी प्रणव सेन का कहना है कि जीडीपी का अनुमान लगाने के लिए एमसीए-21 डाटाबेस का इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित है। इसकी वजह यह है कि जीडीपी की पुरानी सीरीज की तुलना में नई सीरीज में कॉरपोरेट सेक्टर का अनुमान लगाने के लिए कई गुना ज्यादा कंपनियों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जागरण पाठशाला

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) ने हाल में सेवा क्षेत्र के उद्यमों का तकनीकी सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट जारी कर कहा कि 'एमसीए-21' डाटाबेस में शामिल कुछ कंपनियों का जमीन पर अता-पता नहीं है। यह डाटाबेस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका इस्तेमाल जीडीपी का अनुमान लगाने में किया जाता है। 'एमसीए-21' क्या है? जागरण पाठशाला के इस अंक में हम यही समझने का प्रयास करेंगे।

इंजीनियरिंग निर्यातकों को स्टील उपलब्धता पर बनेगी समिति

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यातकों को स्टील की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) के तहत बनेगी, जिसमें इंजीनियरिंग क्षेत्र के भी सदस्य होंगे।

एक अधिकारी ने कहा कि समिति दो महीनों के भीतर स्टील व वाणिज्य मंत्रालयों को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह समिति ऐसे तरीके सुझाएगी जो स्टील उत्पादक और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातक दोनों के लिए लाभकारी होंगे। समिति के गठन का फैसला पिछले सप्ताहभर पहले स्टील व वाणिज्य मंत्रालयों के अधिकारियों और निर्यातकों की बैठक में लिया गया।

इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यातक लगातार यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय भाव पर स्टील मिले, क्योंकि घरेलू बाजार में इसका भाव ज्यादा है। दूसरी तरफ स्टील उत्पादकों का कहना है कि लागत मूल्य और ढुलाई का खर्चा ज्यादा होने की वजह से वे भी भाव कम करने में असमर्थ हैं।

देश छोड़ने वाले अमीरों में भारतीय तीसरे नंबर पर

- पहले स्थान पर चीन और दूसरे स्थान पर रूस है
- पिछले साल 5,000 अमीर लोग भारत की नागरिकता छोड़ किसी और देश में जा बसे

नई दिल्ली, आइएएनएस : कारोबारी सहूलियत रैंकिंग में सुधार और दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था जैसे बड़े-बड़े दावों के बावजूद एक सच्चाई यह सामने आई है कि बड़ी संख्या में भारत के अमीर लोग दूसरे देश चले जाते हैं। एएफआरएशिया बैंक और रिसर्च फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की ताजर रिपोर्ट 'ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू (जीडब्ल्यूएमआर) 2019' में कहा गया है कि पिछले साल देश की नागरिकता छोड़कर कहीं और जा बसने वाले अमीरों के मामले में भारत तीसरे नंबर पर है। ऐसे हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनडब्ल्यूआइ) यानी अमीरों की संख्या गत साल करीब 5,000 थी। यह देश के कुल एचएनडब्ल्यूआइ का दो फीसद है।

अमीरों द्वारा छोड़ दिए जाने वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर चीन है। अमेरिका के साथ ट्रेड वार का असर चीन पर दिखने लगा है। अमेरिका द्वारा नया शुल्क थोपे जाने के बाद चीन पर आने वाले समय में और भी गंभीर असर हो सकता है। सूची में दूसरे स्थान पर रूस है। रूस की अर्थव्यवस्था भी अनेक आर्थिक प्रतिबंधों से प्रभावित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश छोड़ने वाले अमीरों के लिए सबसे आकर्षक गंतव्य हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यहां आर्थिक असमानता काफी अधिक है। भारत की कुल संपत्ति का 48 फीसद हिस्सा एचएनडब्ल्यूआइ के हाथ में है। जबकि इस मामले में पूरी दुनिया का औसत 36 फीसद है।

रिपोर्ट में भारत की सराहना करते हुए हालांकि यह भी लिखा गया है कि अगले 10 साल में भारत की कुल संपत्ति में तेजी से इजाफा होने वाला है। जीडब्ल्यूएमआर रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति सृजन के मामले में भारत ब्रिटेन और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा और 2018 तक यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संपत्ति बाजार बन जाएगा।

संपत्ति सृजन में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद की अग्रणी भूमिका

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अगले 10 साल में संपत्ति सृजन में दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद की अग्रणी भूमिका रहेगी। दिल्ली अपनी विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था व कई अन्य सेक्टरों की अपनी ताकत के बल पर संपत्ति सृजन में योगदान करेगा। बेंगलुरु के पास आइटी और आरएंडडी उद्योग की ताकत है। हैदराबाद देश की फार्मास्यूटिकल राजधानी होने के नाते और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) के बल पर देश के संपत्ति सृजन में योगदान करेगा।

स्पाइसजेट के खिलाफ नहीं चलेगी इन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया

- परिचालन कर्जदाता कंपनी रैम्को सिस्टम्स ने दाखिल की थी याचिका
- याचिका को खारिज करने के एनसीएलटी के फैसले को एनक्लैट ने रखा बरकरार

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्पाइसजेट पर इन्सॉल्वेंसी प्रक्रिया चलाने की एक याचिका को नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल (एनक्लैट) ने खारिज कर दिया। यह याचिका रैम्को सिस्टम्स लिमिटेड ने दाखिल की थी, जो स्पाइसजेट की परिचालन कर्जदाता कंपनी है। चेयरमैन एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश को बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि इस तरह की याचिका में कर्ज और डिफॉल्ट के ठोस प्रमाण चाहिएं, जो कि इस मामले में मौजूद नहीं है। इसलिए एनसीएलटी ने रैम्को सिस्टम्स की याचिका को खारिज कर सही फैसला दिया है।

एनक्लैट ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रैम्को सिस्टम्स ने इन्वॉयस से संबंधित जो डिमांड नोटिस भेजा, उसे स्पाइसजेट ने फॉरवार्ड किया या उसने स्वीकार किया। इसलिए इस मामले में कोई राहत नहीं दी जा सकती। रैम्को सिस्टम्स ने एविएशन सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की आपूर्ति करने के लिए मई 2013 में स्पाइसजेट से एक समझौता किया था। इसके बाद जुलाई 2014 में दोनों पक्षों ने 'चेंज ऑर्डर डिमांड' को अंजाम दिया, जिसमें पूराने समझौते में कुछ संशोधन किए गए।

रैम्को सिस्टम्स के वकील ने एनक्लैट से कहा कि स्पाइसजेट को जनवरी 2016 में 62.89 लाख रुपये का एनवॉयस ई-मेल से भेजा गया था। इसके जवाब में स्पाइसजेट ने कहा कि ये सभी दावे 2013-14 के एनवॉयस पर आधारित हैं और इन्हें वसूल किए जाने की अवधि बीत चुकी है। इसके बाद रैम्को ने 24 अप्रैल 2017 को एक डिमांड नोटिस भेजा, जिसमें कर्ज का कोई एनवॉयस अटैच नहीं किया गया था। स्पाइसजेट ने साथ ही कहा कि 23 जुलाई 2014 की तिथि वाले 59.83 लाख रुपये और 33.70 लाख रुपये के दो डिमांड नोटिस रैम्को सिस्टम्स ने कभी भेजे ही नहीं थे।

एरा इन्फ्रा के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी याचिका खारिज

नई दिल्ली : नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एरा इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड के विरुद्ध आइसीआइसीआइ बैंक की इन्सॉल्वेंसी याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका को दावों में दोहराव के आधार पर खारिज किया गया। एनसीएलटी के प्रेसिडेंट जस्टिस एमएम कुमार की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि आइसीआइसीआइ बैंक ने पहले ही एरा इन्फ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) लिमिटेड की पैरेंट कंपनी एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग के विरुद्ध इसी प्रकार के दावे किए हुए हैं, जिस पर अभी समाधान प्रक्रिया चल रही है।

चीन ने डील में देरी की तो बुरा हाल करूंगा : ट्रंप

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन ने निकट भविष्य में ही ट्रेड वार खत्म करने के लिए डील नहीं की और यह मामला उनके दूसरे कार्यकाल (2020 के बाद) तक पहुंचा, तो वे चीन का बुरा हाल कर देंगे। दूसरी तरफ, चीन ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ कारोबारी विवाद सुलझाने के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन इसके लिए चीन अपने सिद्धांत जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की कुर्बानी नहीं देगा।

ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा कि कारोबारी वार्ता के पिछले कुछ चरणों में चीन की इतनी दुर्गति हो चुकी है कि वे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुनाव तक भी इंतजार कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि वे जानते हैं कि बेहतरीन अर्थव्यवस्था, रोजगार के बेहतर आंकड़ों और अन्य बहुत सी चीजों के दम पर मैं ही जीतने वाला हूं। ऐसे में अगर उन्हें मेरे दूसरे कार्यकाल में डील करनी पड़ी, तो उनके लिए और बुरा हाल होगा। इसलिए उनके लिए बेहतर यही है कि वे अभी डील कर लें। वहीं, चीन के अखबार पीपुल्स डेली में सोमवार को प्रकाशित होने के लिए तैयार एक लेख में कहा गया है कि चीन लड़ाई के पक्ष में भी नहीं है। लेकिन अगर उसे इसमें उतरना ही पड़ा, तो वह पीछे नहीं हटेगा।

चीन के ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को कहा कि अगर ट्रेड वार गहराता है, तो वार्ता की मेज पर अमेरिका का पक्ष कमजोर होगा। दो दिन पहले अमेरिका ने चीन से आयातित सभी सामानों पर शुल्क बढ़ाकर कम से कम 25 फीसद कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने इस वर्ष जून में ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की उम्मीद जताई है।

हिंदुजा बंधु तीसरी बार ब्रिटेन के सबसे बड़े धनकुबेर बने

- इससे पहले वर्ष 2014 और 2017 में हिंदुजा बंधु आए थे शीर्ष पर
- पिछले वर्ष पहले स्थान पर रहने वाले जिम रैटक्लिफ तीसरे स्थान पर फिसले

लंदन, आइएएनएस : अरबपति हिंदुजा बंधुओं श्रीचंद हिंदुजा व गोपीचंद हिंदुजा ने तीसरी बार ब्रिटेन के सबसे बड़े धनकुबेर का तमगा हासिल किया है। संडे टाइम्स रिंच लिस्ट के मुताबिक पिछले वर्ष हिंदुजा बंधुओं की संपत्ति में 135.6 करोड़ पाउंड (12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) का इजाफा हुआ है। इस बढ़त के बाद हिंदुजा बंधुओं की संपत्ति 2,200 करोड़ पाउंड (करीब दो लाख करोड़ रुपये) पर पहुंच गई। इससे पहले वर्ष 2014 और 2017 में हिंदुजा बंधु इस सूची में पहले स्थान पर रहे थे।

ब्रिटेन के 1,000 धनकुबेरों की सूची में मुंबई में जन्मे डेविड और सिमोन रियूबेन बंधु इस वर्ष दूसरे स्थान पर रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति 1,866 करोड़ पाउंड (लगभग 1.70 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है। पिछले वर्ष की सूची में पहले स्थान पर आने वाले जिम रैटक्लिफ इस वर्ष तीसरे स्थान पर फिसल गए हैं। उनकी संपत्ति में 290 करोड़ पाउंड (26,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) की गिरावट आई है। सूची के प्रकाशक ने कहा कि ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन (ईयू) से बाहर हो या नहीं हो, गोपीचंद हिंदुजा का ब्रिटेन से लगाव कम नहीं होने वाला है।

इस सूची में पिछले वर्ष पांचवें स्थान पर रहने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल इस वर्ष 11वें स्थान पर फिसल गए हैं। सूची के मुताबिक मित्तल की कुल संपत्ति अभी 1,066 करोड़ पाउंड (96,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) है। उनके बाद सूची में खनन उद्योग के दिग्गज अनिल अग्रवाल का नाम है, जिनकी संपत्ति 1,057 करोड़ पाउंड (95,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) आंकी गई है। सूची में भारतीय मूल के करीब 45 धनकुबेरों के नाम हैं। इनमें प्लास्टिक उद्योग के दिग्गज श्रीप्रकाश लोहिया, ट्रांसपोर्ट और फूड बिजनेस कारोबारी सुनील वासवानी और केयर होम व होटल कारोबारी लॉर्ड डोलार पोपट भी शामिल हैं।

ऐसे होता है यह सर्वे : संडे टाइम्स रिच लिस्ट में धनकुबेरों की पहचान की जाने लायक संपत्तियों के मूल्य का आकलन किया जाता है। इनमें भूमि, प्रॉपर्टी, कंपनियों के शेयर और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। इसमें उन धनकुबेरों के बैंक अकाउंट्स में जमा रकम शामिल नहीं है।

ऐसी है हिंदुजा बंधुओं की शख्सीयत

हिंदुजा बंधु चार भाई हैं। इनमें लंदन निवासी श्रीचंद हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा दुनियाभर में हिंदुजा ग्रुप के तहत तेल व गैस, बैंकिंग, आइटी व प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं। दोनों भाई निर्यात कारोबार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1979 में लंदन आए थे। उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के ओल्ड वार ऑफिस का वर्ष 2014 में 35 करोड़ पाउंड (3,150 करोड़ रुपये) में अधिग्रहण कर लिया। इसे वे एक लक्जरी होटल में तब्दील कर रहे हैं जिसके अगले वर्ष तैयार हो जाने की उम्मीद है। तीसरे भाई प्रकाश हिंदुजा स्विट्जरलैंड के जेनेवा में फाइनेंस का कारोबार संभालते हैं। चौथे भाई अशोक हिंदुजा भारत में ग्रुप के कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि हिंदुजा ग्रुप की स्थापना परमानंद हिंदुजा ने मुंबई में वर्ष 1914 में की थी।

निगाहें

इस सप्ताह थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आएंगे, शुक्रवार को आए औद्योगिक आंकड़ों की प्रतिक्रिया सोमवार को बाजार पर दिखेगी

ट्रेड वार और आम चुनाव से बाजार को मिलेगी दिशा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के शेयर बाजारों की दिशा इस सप्ताह अमेरिका और चीन के ट्रेड वार से जुड़े घटनाक्रम, प्रमुख आर्थिक आंकड़ों, कंपनियों के तिमाही परिणाम और चुनाव से जुड़ी गतिविधियों से तय होगी। सैमको सिक्युरिटीज एंड स्टॉकनोट के संस्थापक और सीईओ जिमीत मोदी ने कहा कि इस सप्ताह का महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ट्रेड वार, चुनाव से जुड़े घटनाक्रम और तिमाही नतीजों में से किसका बाजार पर सर्वाधिक असर होगा। तिमाही नतीजे के रुझान को मोटे तौर पर भाप लिया गया है, इसलिए ट्रेड वार और चुनाव बाजार को अपनी-अपनी दिशा में खींचने की कोशिश करेंगे।

इस सप्ताह थोक और खुदरा महंगाई दर के आंकड़े आएंगे। आम चुनाव के लिए आखिरी मतदान आगामी रविवार को होना है। आइटीसी, एचडीएफसी लिमिटेड, ल्यूपिन, बजाज ऑटो और हिंडाल्को के तिमाही परिणाम इस सप्ताह आएंगे। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए कमजोर औद्योगिक आंकड़ों की प्रतिक्रिया भी सोमवार को दिख सकती है।

अमेरिका और चीन की वार्ता का फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला है। अमेरिकी की तरफ से चीन के अतिरिक्त आयात पर शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। चीन ने इस पर जवाबी कदम उठाने की चेतावनी दी है। यह स्थिति बाजार में निवेश बढ़ने की दमदार तस्वीर प्रस्तुत नहीं करती है।

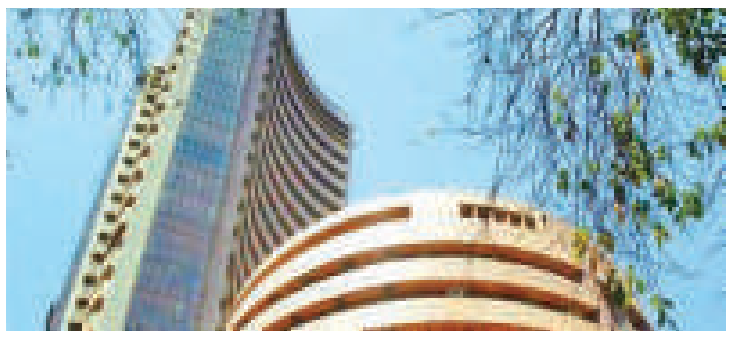

नौ ब्लूचिप कंपनियों का एमकैप 1.60 लाख करोड़ घटा : गत सप्ताह के कारोबार में देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से नौ के बाजार पूंजीकरण (एमकैप) में 1.60 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) एमकैप में बढ़ोतरी दर्ज करने वाली अकेली कंपनी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) का एमकैप सर्वाधिक 99,212.9 करोड़ रुपये घटा। एचडीएफसी बैंक का एमकैप 19,634 करोड़ रुपये, एचडीएफसी का 13,573.5 करोड़ रुपये, आइसीआइसीआइ बैंक का 10,974.8 करोड़ रुपये और आइटीसी का 7,232.6 करोड़ रुपये घटा। कोटक महिंद्रा बैंक का एमकैप 4,409.41 करोड़ रुपये, इन्फोसिस का 3,364.07 करोड़ रुपये, एचयूएल का 1,233.88 करोड़ रुपये और एसबीआइ का एमकैप 981.71 करोड़ रुपये घट गया। दूसरी ओर टीसीएस के एमकैप में 1,144.48 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। टीसीएस सर्वाधिक 8,01,340.52 करोड़ रुपये के एमकैप के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी रही। टीसीएस ने गुरुवार को देश की सबसे बड़ी कंपनी का तमगा आरआइएल से छीना लिया था।

एफपीआइ ने इस महीने अब तक 3,207 करोड़ रुपये निकाले

नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय ट्रेड वार और चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता के बीच इस महीने अब तक के सात कारोबारी सत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने भारतीय पूंजी बाजार (शेयर और डेट बाजार) से 3,207 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दो से 10 मई के बीच एफपीआइ ने शेयर बाजार में 1,344.72 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने डेट बाजार में 4,552.20 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री की।

एनबीएफसी सेक्टर के सामने भीषण संकट : श्रीनिवास

- कॉरपोरेट मामलों के सचिव ने कहा, देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए यह परीक्षा की घड़ी है
- जिम्मेदार कंपनियां जोखिमों का बेहतर प्रबंधन कर रही हैं और उन्हें संकट से नहीं निपटना पड़ेगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (एनबीएफसी) के सामने भीषण संकट खरा है। कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा कि कुछ बड़ी कंपनियों के बड़े दांव विफल हो गए हैं और इस सेक्टर के सामने कर्ज की भी बड़ी किल्लत हो गई है। इससे यह सेक्टर विनाश के कगार पर पहुंच गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आइएलएंडएफएस) समूह की वित्तीय त्रासदी और कुछ अन्य बड़ी कंपनियों की ओर से हुए डिफॉल्ट के बाद देश का वित्तीय सेक्टर अचानक अनेक संकटों से घिर गया है।

श्रीनिवास ने कहा कि सेक्टर के सामने भीषण संकट खड़ा है। कर्ज नहीं मिल रहे हैं। कंपनियों ने पहले से ही भारी-भरकम कर्ज ले रखे हैं। संपत्तियों और देनदारियों में भारी असंतुलन है। इसके अलावा कुछ विशालकाय कंपनियों के कुछ बड़े दांव विफल हो गए। इससे विनाश की पूरी परिस्थिति तैयार हो गई है।

उन्होंने साथ ही कहा कि जिम्मेदार कंपनियां जोखिमों का अच्छी तरह से प्रबंधन कर रही हैं और उनके सामने ऐसी गंभीर स्थिति से निपटने की नौबत नहीं आएगी। देश में कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। यह निर्णायक क्षण है। जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, उस हिसाब से मध्य से लेकर लंबी अवधि में अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। छोटी अवधि में हालांकि संकट की स्थिति है। एनपीए की स्थिति को बाहरी कारणों से जोड़े जाने के मुद्दे पर श्रीनिवास ने कहा कि यह वाजिब तर्क नहीं है। जिम्मेदार व्यवहार भी कोई चीज होती है। इस महीने के शुरू में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर में भारी तनाव है। कुछ बड़ी गलतियों को सुधारकर स्थिति को संभाला जा सकता है।